

ख़बर संक्षेप

संदिग्ध स्थिति में फांसी से लटकी पाई गई युवक की लाश

हरिभूमि न्यूज/ गा ड र वा रा । समीपस्थ ग्राम जमाड़ा के पास जब लोगों ने एक युवक की फांसी पर लटकी हुई लाश देखी तो सनसनी का महौल निर्मित होने से नही चूक पाया। वही घटना की जानकारी जब पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा देखा गया तो मृतक की पहचान नीरज शुक्ला ानवासी ग्राम झंझनखेड़ा के रूप में की गई। वही दूसरी ओर मौके पर घटना की सच्चाई को देखते हुये युवक की फांसी चर्चा का विषय बनने के साथ साथ मामले को संदिग्ध बनाने में कोई कसर छोड़ रही है...? घटना को लेकर पुलिस द्वारा मार्ग कायम करते हुये मामले को जांच में लेते हुये अलग अलग षंडुओं पर जांच शुरू कर दी गई है।

अब बसेडिया द्वारा शुरू किया असहाय व निराश्रित वृद्धजनों मच्छरदानी वितरण कार्यक्रम



हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। सेवा कार्यों में सदैव अग्रणी रहने वाले मुकेश बसेडिया द्वारा प्रति वर्ष के अनुसार इस साल भी क्षेत्र के समाज सेवी बसेडिया ने बर्षा ऋतु के शुरू होते हुये जंगल क्षेत्र की दुर्गम पहाड़ी वनग्रामो सहित शहर के असहाय व निराश्रित वृद्धजनों व दिव्यांगों हेतु मच्छरदानी वितरण का प्रारंभ बैटियो के पैर पखारकर व शिक्षा प्रोत्साहन हेतु शिक्षण सामग्री भेंट कर किया। बताया जाता है कि परंपरा अनुसार पश्चिम बंगाल कलकत्ता के दिव्य शक्ति पीठ महाकाली के दरबार में उपस्थित वृद्ध माताओं व दिव्यांग जनों का सम्मान कर उन्हें मच्छरदानी व सा डियों वस्त्र आदि प्रदान कर आशीर्वाद लिया। मैयारानी विजयासन व श्री दादाजी धूनी वालो की असीम कृपा से प्रतिवर्ष किसी न किसी पावन धाम से मच्छरदानी वितरण का शुभारंभ कर सतत दुर्गम पहाड़ी वनग्रामो ,गाडरवारा शहर के निराश्रित वृद्ध जनों व विभिन्न तीर्थ स्थलों पर असहाय, दिव्यांग जनों को लगातार चार माह वर्षा ऋतु में मच्छरदानी प्रदान की जाती है। बसेडिया ने बताया कि उपरोक्त सेवा का मुख्य उद्देश्य वृद्ध जनों को सुख चैन की नींद सुलाना तथा मच्छर व वर्षा जनित बीमारियों से बचाव है ।उपरोक्त सेवा कार्य विगत 2004 से बाइस वर्षों से वर्षा ऋतु में मच्छरदानी तथा शीघ्रण उड शरद ऋतु में कंबल ,रजाई वितरण तथा ग्रीष्म ऋतु में गुड़ चना युक्त प्याऊ जल सेवा व गौ जल सेवा निरंतर चल रही है।

आंगनबाड़ियों में मंगल दिवस योजना बदहाल, सक्षम अधिकारियों की कार्यशैली पर खड़े हो रहे सवाल?

हरिभूमि न्यूज/ साईंखेड़ा। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएँ अपने गंतव्य स्थानो पर पहुंचा तो बी जाती है। किन्तु उसके संचालन के लिए जिज अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाती है व पूरे तरह से लापरवाही को भेंट चढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही जनपद पंचायत साईंखेड़ा क्षेत्र की अनेक आंगनवाडियों में देखने को मिल रहा है। जहां मंगल दिवस योजना अमंगल दिवस बनती हुई नजर आ रही है; दर अखल आंगनवाडी केन्द्रों मे पोषण आहार योजनातर्गत हर माह के मंगलवार के दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। किन्तु इन कार्यक्रमो में भी जमक़र पत्नीता लगाते हुए जान पड़ रहा है; ग्रामीण क्षेत्रों में जन वर्चोओं के माध्यम से किल नही जानकारियों के अनुसार अनेक आंगनवाडियों में यह योजनाए बराबर संचालित नही होती है, जिसमें देखा जावे तो सबसे दुरगन्ना हालत ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों के आंगनवाडी केन्द्रों की है जहां न तो विभाग के अधिकारी और न ही कोई कर्मचारी निरीक्षण करने पहुंचता है; ऐसे में नाम मात्र की कार्रवाई कर दी जाती है। इन्ही आंगनवाडियों की स्थिति को सच्चाई पर गौर किया जाए तो वे बदहाल स्थिति से जुझ रही है न वहां बैठने को ही पर्याप्त व्यवस्था है और न ही सामान रखने की है। वहीं कुछ आंगनवाडी भवनों की हालत जर्जर हो चुकी तो कुछ टूटे मकानों में संचालन हो रहा है। इस तमाम बातो पर ध्यान तो ऐसे में योजनाओं का संचालन कैसा होगा यह स्वयं सिद्ध है, पर्याप्त मात्रा में आने वाली राशि कब और कित्पर जा रही है इसका कोई पता भी नही, जिज कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए उसके लिए सामग्री भी नही मिलती और मिलती भी है तो गायब हो जाती है। आंगनवाडियों के माध्यम से बच्चो, महिलाओं और किशोरी बालिकाओं की देखभाल और उनके स्वास्थ्य मे सुधार लाने के लिए जो तेयारियां की गई है उसमें दिल चपपी ना तो आंगनवाडियों की कार्यकर्ता और सहायिकाओं में है और ना ही अधिकारियों में, आंगनवाडियों में मंगल दिवस योजना पोषण आहार योजना वर्ष 2007-०8 के तहत बनाई गई है, जिसके तहत हर माह के मंगलवार को अलग अलग कार्यक्रम करना है, प्रथम मंगलवार को गोद भराई, दूसरे में अन्न प्राशन, तीसरे में जन्म दिवस और चौथे मंगलवार को किशोर बालिका दिवस मगाना है। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चो की उपस्थिति बढ़ाना, सुरक्षित प्रसव, मातृ एवं शिशु मृत्युदर में कमी कुपोषण कम करना, किशोरी बालिकाओं को आयरन फोलिक एसिड व डी वार्मिंग की गोेलिया वितरण करना है। मंगल दिवस योजना का क्रियान्वयन बराबर न होने से संबंधित क्षेत्रो में भी लोगो को इन केंद्रो पर मरोखा उठ रहा है, बदहाल और बच्चो को बराबर ध्यान न दिये जाने के चलते यहां कार्रवाई होना विहायत जबर्यो हो गई है।

सोसाईटी का माल बिक रहा किराना दुकानों पर बिचौलिया हो रहे मालामाल

हरिभूमि न्यूज/चीचली। शासन द्वारा गरीबी रेखा एवं अति गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए सेवा सहकारी समितियों से सस्ता अनाज उलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो इस योजना में शामिल हितवाहियों को शासन द्वारा एक रुपया किराा गेहू व चावल हर माह प्रदान किये जा रहे हैं। मगर वही दूसरी ओर देखा जा रहा है कि इस प्रकार से खाद्यान्न वितरण केन्द्रों के ठीक सामने कुछ बिचुरियां नुमा लोगों द्वारा अपनी अनाज खरीदने की दुकान लगाते हुये उन गरीबों को प्रलोभन देते हुये उनका माल सस्ते दामों में खरीदते हुये उसे बाजार में महंगा बेचते हुये मालामाल होने से नही चूक पा रहे है; इस प्रकार से खाद्यान्न वितरण केन्द्रों का संचालन होने वाले अनाज खरीदी करने वाले दुकानों की सच्चाई से प्रभावितक अधिकारी भी अनजान नही है। मगर किसी भी प्रकार को कारवाही नही होने के कारण उनके हैसले लगातर बुलंद होते हुये दिखाई देने से नही चूक पा रहे है, जिसके चलते उपरोक्त को शासकीय दुकानों से मिलने वाले अनाज पर इस प्रकार से बिचुरियानुमा लोग अपनी कूटिज जमाये हुये मालामाल होते हुये दिखाई दे रहे है।

पुलियों पर निकल रही लोहे की राडे दे रही दुर्घटनाओं खुला को आमंत्रण...

करोड़ों की राशि से निर्मित सीमेन्ट सड़क की गुणवत्ता चंद सालों के अंदर ही उभरकर आने लगी सबके सामने

हरिभूमि न्यूज/बारहाबड़ा। जहां विकास के नाम पर करोड़ो रूपया खर्च किये जाते है, मगर विकास कार्य के दौरान अधिकारियों द्वारा बरते जाने वाली उदासीनता का परिणाम इस तहर से देखने मिलता है कि शासन की राशि बर्बाद होने से नही चूक पाती है...? कुछ इसी प्रकार की सच्चाई चीचली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सूखाखैरी से बारहाबड़ा होते हुये सालीचौका तक मात्र कुछ साल पहले लगभग 76 करोड़ रूपया की लागत से निर्मित हुई सीमेन्ट सड़क को देखते हुये जान पड़ रहा है ? बताया जाता है कि इस सीमेन्ट सड़क गुणवत्ता को लेकर तो सबाल निर्माण के शुरूआती दौर में ही उठनान शुरू हो गये थे। क्योंकि जब इस सीमेन्ट सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो उस दौरान निर्माण कार्य करने वाली कंपनी द्वारा छोटी मोटी पुलियों के निर्माण से शुरूआत की गई थी। जिसके चलते ग्राम बारहाबड़ा के पास निर्माणाधीन एक पुलिया निर्माण के दौरान ही धराशाही होने से निर्माण कार्य की सच्चाई उजागर होते हुये दिखाई पड़ने से नही चूक पा रही थी। इस सच्चाई को उस दौरान हरिभूमि द्वारा समय समय पर प्रमुखता से उजागर किया गया था। मगर संबंधित विभाग द्वारा किसी भी प्रकार से ध्यान नही देने का परिणाम इस तरह देखने मिला कि निर्माण कार्य करने वाली कंपनी द्वारा करोड़ो की राशि से बनाई गई इस सड़क निर्माण में अपनी मनमानी के सभो हद्दे पार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी...? सीमेन्ट सड़क की एक ओर की पट्टी बनने के बाद जब दूसरी ओर की पट्टी का कार्य शुरू ही हुआ था और हाल में में निर्मित की गई सड़क की पट्टी जहां तहा से चिटकते हुये दिखाई देकर अपनी गुणवत्ता को



उजागर करने लगी थी यानि की सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण ही नही हो पाया था कि निर्माणाधीन सड़क पर जहां तहां से निकल रही दरारे तथा चटकती हुई सड़क निर्माण कार्य में अपनाई जाने वाली गुणवत्ता की सच्चाई को खुलकर उजागर करते हुये देखी जा रही थी। उस दौरान इस सच्चाई को हरिभूमि द्वारा लगातार उजागर किये जाने के बाद भी संबंधित विभाग द्वारा किसी भी प्रकार से ध्यान नही दिये जाने के कारण जहां करोड़ो की राशि से बनी यह सड़क निर्माण के दौरान से अधिकारियों की अनदेखी व निर्माण कार्य करने वाली कंपनी की मनमानी की भेंट चढ़ने से नही चूक पाई है...? इतना ही नही यदि 76 करोड़ रूपया की लागत से बनाई गई इस सड़क के अन्य निर्माण कार्यों पर नजर डाली जावे तो सड़क निर्माण के दौरान सूखाखैरी से बारहाबड़ा होते हुये सालीचौका के बीच सीमेन्ट सड़क का निर्माण कार्य करने के साथ साथ बीच में पड़ने वाली पुलियों का निर्माण कार्य भी इसी में शामिल होने की चर्चा सुनी जा रही है..? मगर इस इस सड़क पुलिये जहां निर्माण के दौरान ही जहां तहां से चटकते हुये देखी जा रही थी



और वर्तमान समय में यानि की इस निर्माण को अभी मात्र कुछ साल का समय भी नही बीत पाया है और पुलियों के आलवा सड़क में जहां तहां निकल रहे गड्डे निश्चित तौर से संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्य प्रणाली को कटघरे में खड़ा करने से नही चूक पा रहे है तो दूसरी ओर पुलियों के ऊपर का हाल इस तरह से देखने मिल रहा है कि निर्माण के दौरान उपयोग की गई लोहे की सामग्री सड़क के बीचों बीच निकलते हुये अपनी गुणवत्ता को उजागर करने के साथ साथ बड़ी दुर्घटनानओं को आमंत्रण देने से नही चूक पा रहा है...? वही बताया जाता है कि सड़क निर्माण का कार्य जिस प्रकार से पुलियों का नया निर्माण करने की जगह कंपनी द्वारा पुराने पुल व पुलियों के भरोसे ही पूर्ण किया जाना संपूर्ण क्षेत्र में चर्चा का विषय बनने से नही चूक रहा है? प्रमुख रूप से देखा जावे तो ग्राम बारहाबड़ा के समीप ऊमर नदी पर बने हुये पुल जिसके निर्माण को वर्षों बीत जाने के कारण जहां यह पुल जर्जर स्थिति में पहुंच जाने के बाद भी इस पुल का पुनः निर्माण होने की जगह मात्र उसे रंग रोकन करते हुये इस 76 करोड़ा रूपया की सड़क



की जिन्दगी इस पुल के भरोसे ही छोड़ दिये जाने का परिणाम इस तरह से देखने मिल रहा है कि शासन की करोड़ो रूपया की राशि खर्च हो जाने के बाद जहां सड़क के साथ साथ अनेक पुल व पुलिया मात्र एक साल के अंदर ही टूटना शुरू हो चुकी थी तो दूसरी ओर सड़क पर जहां तहां निकल रही लोहे की राडे वाहन चालको को खुलेआम मौत का आमंत्रण देने से नही चूक पा रही है..? इस प्रकार से सरकार द्वारा क्षेत्रवासियों को यातायात के लिये अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने व युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त करने की सोच को ध्यान में रखते हुये ग्राम सूखाखैरी से बारहाबड़ा होते हुये सालीचौका पौड़ार तिरहा तक लगभग 76 करोड़ की लागत से सीमेन्ट सड्क का निर्माण कराया गया था। वह निश्चित तौर से विभाग के अधिकारियों की अनदेखी व मिली भगत के चलते तथा क्षेत्र के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण निश्चित तौर से प्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से नही चूक पाया है..? क्योंकि करोड़ो रूपया की राशि से निर्मित हुई यह सीमेन्ट सड़क जिस तरह मात्र कुछ के उपरांत जिस तरह से टूटते हुये



देखी जा रही है वह एक बड़ी गफलतबाजी की ओर संकेत देने से नही चूक रही है..? इसी बात को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा उच्च स्तर की जांच की मांग उठाना शुरू कर दिया गया है। इस तरह इस सड़क को बने हुये कुछ साल ही निकले है और जहां तहां बड़े गद्दे के रूप में दिखाई देने लगी है तो अनेक जगहों पर निकल रही लोहे की राडे राहगीरों के लिये खुलेआम मौत का सायरन बजाने से नही चूक रही है? इस सच्चाई को हरिभूमि द्वारा लगातार उजागर किये जाने के बाद भी न तो यहां के जिम्मेदारों द्वारा ध्यान दिया गया है और न ही संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा जिसका परिणाम है कि क्षेत्र के लिये शासन से मिली करोड़ो की सौगत मात्र बंदर बांट की भेंट चढ़कर बर्बाद होने से नही बच पाई है? यदि उस समय भी क्षेत्र के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों द्वारा टूट रही सड़क की सच्चाई पर अपनी गंभीरता का परिचय देते हुये इस सड़क निष्ठा के साथ जांच कराने के लिये आगे आये होते तो निश्चित तौर से निर्माण कार्य करने वाली कंपनी के साथ साथ मलाई खाने वाले अनेक अधिकारी बेनकाब होने से नही चूक पाते...?

तीन चिकित्सकों सहित प्रभारी अधिकारी को दिया नोटिस

सीएमएचओ का नगर के शासकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। नगर के शासकीय च्चिकित्सालय में फैल रही अव्यवस्थाओं से लेकर च्चिकित्सको की कार्य प्रणाली के चलते जहां स्वास्थ्य विभाग की साख को बड़ा लगते हुये ाइखाई देने से नही चूक रहा है तो दूसरी ओर मीडिया पर खबरे आने के चलते अधिकारियों की भूमिका पर भी सबाल खड़े होने से नही चूक रहे है। इसी के चलते बीते हुयेदिव जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष कुमार मिश्रा ने नगर के सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का विस्तृत जायजा लिया। बताया जाता है कि इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला एवं पुरुष वार्ड, लेबर रूम, ओपीडी तथा अस्पताल की साफ-सफाई व्यवस्था का अवलोकन किया और भर्ती मरीजों से चर्चा कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। वहीं दूसरी ओर अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान गर्भवती महिलाओं की जांच एवं प्रसव व्यवस्थाओं की समीक्षा में यह सामने आया कि फरवरी 2026 से 16 जुलाई 2026 तक अस्पताल में 243 सिजेरियन प्रसव किए गए, जो निर्धारित मानकों की तुलना में अधिक पाए गए। इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए डॉ. मिश्रा ने डॉ. अनामिका जैन, डॉ. क्षिरा कौरव एवं डॉ. शिवानी सिंह को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सीएमएचओ ने स्पष्ट किया कि सिजेरियन प्रसव केवल चिकित्सकीय आवश्यकता होने पर ही किया जाए तथा प्रत्येक गर्भवती महिला के लिए पहले सुरक्षित सामान्य प्रसव को प्राथमिकता दी जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सकीय निर्णय मरीज के हित और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप ही लिए जाने चाहिए। डॉ. मिश्रा ने कहा, “चिकित्सकों को भगवान का दर्जा दिया जाता है और मानव सेवा हमारा सर्वोच्च धर्म है।



यदि किसी भी शासकीय स्वास्थ्य संस्था में अनावश्यक सिजेरियन, लापरवाही या नियमों के विपरीत कार्य पाए गए, तो संबंधित दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।” निरीक्षण के दौरान कुछ लोगों द्वारा प्रसव अथवा अन्य सेवाओं के बदले धनराशि लेने की मौखिक शिकायत भी सामने आई। इस पर सीएमएचओ ने शिकायतकर्ताओं से लिखित शिकायत प्रस्तुत करने का आग्रह किया और आश्चस्त किया कि जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा रात्रिकालीन इयूटी में महिला चिकित्सकों की तैनाती निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर प्रभारी अधिकारी डॉ. उपेन्द्र वास्तकार को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही निर्देश दिए गए कि भविष्य में शासन के निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही इयूटी लगाई जाए, ताकि मरीजों को बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। सीएमएचओ ने कहा कि इस तरह सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे।

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी और विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल ने शनिवार को ग्राम पंचायत लिलवानी में विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत पूजन-अर्चन कर लोकार्पण किया। उन्होंने 49 लाख रुपए की लागत से निर्मित उपस्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही 12 लाख रुपए एवं 4.86 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित बनने वाली सीसी सड़क निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण कर शुभारंभ किया। इन कार्यों से ग्रामवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं एवं आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, उद्योग, कृषि एवं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। जनकल्याणकारी



योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार सतत प्रयासरत है। इस अवसर पर रमाकांत शर्मा, हरिप्रताप ममार, अशोक मिश्रा, भास्कर पटेल, रमेश कौरव, श्रवण कौरव, जिला पंचायत सदस्य धनंजय पटेल, जनपद सदस्य भागवेंद्र कौरव सहित अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

नगर के दूर संचार केन्द्र में लगे मधुमक्खी के छितनों से फैल रही दहशत

हरिभूमि न्यूज/ गाडरवारा। इस समय जहां एक ओर बीएसएनल के उपभोक्ता खस्ताहाल हो रही नेटवर्क व्यवस्थाओं के चलते परेशान हो ही रहे है साथ ही साथ दूर संचार केन्द्र में अन्य फैली हुई व्यवस्थाओं से भी उपभोक्ताओं को संतुष्ट होते हुए नही देखा जा रहा है? क्योंकि इस समय यदि दूसर संचार केन्द्र में देखा जावे तो देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भले ही संपूर्ण देश में स्वच्छता अभियान चलाते हुए शासकीय कार्यालयों के अधिकारियों को अपने सभी कार्यालयों में स्वच्छत वातावरण बनाने के आदेश दिये है। मगर केन्द्र सरकार के अधीन माने जाने वाले दूर संचार केन्द्र इस समय पूर्णरूप से गंदगी के आगोश में समाया हुआ दिखाई पड़ रहा है...? इतना ही नही इस केन्द्र के भवन में लगे हुए मधु मंखियों के छितानों की स्थिति को देखते हुए अपने जरूरी कार्यों से पहुंचने वाले उपभोक्ताओं में दहशत देखने मिल रही है? क्योंकि कस्बो की कुर्सियों के कार्यों में भारी मात्रा में लगे हुए मधु मंखी छितानों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कही यह मधुमंखी किसी के ऊपर हमला न बोल दे यदि ऐसा होता है कि निश्चित ही उसकी जान खतरे से खानी नही रह पायेगी।



पंचायतों में पति राज खत्म करने निर्णय के बाद भी स्थिति में नहीं हुआ सुधार, आज भी पत्नियों की कुर्सी पर जलवा दिखा रहे पतिदेव?

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। जहां एक ओर देखा जा रहा है कि संविधान में महिलाओं को आरक्षण देते हुए उन्हें अग्रसर किया जा रहा है। मगर अक्सर देखा जाता है कि जिन क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ने का प्रयास करती है उन क्षेत्रों में उनके पतियों द्वारा उनकी कुर्सी पर कब्जा करते हुए उन्हें पीछे की ओर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते है? जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो पंचायती राज व्यवस्था से लेकर नगर पालिकाओं पर सरपंच पतियों से लेकर पार्षद पतियों का ही बोलबाला देखने मिलता है, जिसमें प्रमुख रूप से गौर किया जावे तो पंचायती राज में तो महिला सरपंच या जनपद सदस्य मात्र नाम की ही होती है बोलबाला तो उनके पतियों का ही रहता है? यहां तक की सरपंच पतियों द्वारा अपने आप को सरपंच प्रतिनिधि बताने या फिर अपने वाहनों में लिखने से भी नही चूकते है। जबकि नियम के अनुसार तो बताया जाता है कि निर्वाचित प्रतिधिनियों के प्रतिनिधि होने का कालम विधायक तक हो होता है? विधायक के नीचे प्रतिनिधि का कालम होता ही नही है...? मगर इसके बाद भी सरपंच पति अपने आप को सरपंच प्रतिनिधि मानते हुए पंचायतों की कार्यवाही में सबसे आगे देखे जाते है तो कुछ इसी प्रकार का हाल नगर पालिका से लेकर नगर परिषदों का देखने मिलता है जहां पर पार्षद पतियों की मौजूदगी देखी जाती है? इस बात की सच्चाई इस समय क्षेत्र की ग्राम पंचायतों से लेकर नग कार्यालयों से लेकर जनपद व ग्राम पंचायतों में



आसानी से देखने मिल रही है। जहां पर बताया जाता है कि लम्बे अरसे महिला जनप्रतिनिधियों के राज करने की मिसालें पूर्व में मिलती रही है। हालात यह थी कि महिला जनप्रतिनिधियो के पतिदेव इन संस्थाओं के कार्यों में दखलन दाजी का प्रयास तो करते हुये देखे ही जाते है साथ ही कभी कभार इन जिम्मेदार मानी जानी वाली संस्थाओं की बैठकों में भी तशरीफ लाने से भी नही चूकते है। किंतु महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों की मनमानी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगभग दो साल पहले म.प्र. शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत की बैठकों से लेकर अन्य कार्यक्रमों में चुने हुए महिला जनप्रतिनिधियों के साथ उनके सम्बंधियो के शामिल होने पर रोक लगाने के आदेश जारी किये गये थे जिसमें प्रमुख रूप से गौर किया जावे तो स्वायत्तशायी संस्थाओं में महिला जनप्रतिनिधियों के सम्बंधियो के हस्तक्षेप को अनुचित बताते हुए शासन द्वारा लिए गये उक्त निर्णय की लोगों द्वारा सरहना की गई थी और इस निर्णय का पालन करने के लिए संबंधित

विभाग के अधिकारियों के आलवा जिला स्तर के अधिकारियों को जिम्मा भी सौंपा गया था कि इस निर्णय का कठोरता के साथ पालन होना चाहिए। मगर इस आदेश को लगभग एक वर्ष से भी अधिक का समय बीत ही हनन होते बाद ही स्थिति जहां की तहां नजर आ रही है। क्योंकि इस आदेश की ओर न तो प्रशासनिक अधिकारी ध्यान दे रहे है और न ही इसका पालन हो रहा है? जिसके चलते आज भी अनेक जगहों पर महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों द्वारा अपनी पत्नी की कुर्सियों पर जलबे दिखाते हुए आसानी से देखा जा रहा है? इस प्रकार की स्थिति के चलते जहां महिला आरक्षण नियम पर तो प्रश्न लग रही रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार की मंशा अनुसार महिलाओं की स्वतंत्रता की भी हनन होते हुए देखा जा रहा है। इस प्रकार की सच्चाई के चलते जहां अनेक जगहों पर निर्वाचित हुई महिला जनप्रतिनिधि मात्र चौका चूल्हा तक की सीमित होकर रह गई है और उनका निर्वाचित होना मात्र एक औपचारिकता बना हुआ देखने मिल रहा है? जबकि गौर किया जावे तो संविधान में मातृशक्ति को जिस सोच के साथ आरक्षण देते हुए उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया गया है और उसका पूरा लाभ मातृशक्ति को मिलने लगे तो निश्चित तौर से देश की सूरत बदलने में देर नही लग सकती है। मगर और आग्रशान को उदासीनता के चलते संभव होते हुए दिखाई नही पड़ रहा है।

क्षेत्र की सड़कों पर बिना नम्बर के चल रहे सैकड़ों टैक्टर से दुर्घटना की बनी आशंका

हरिभूमि न्यूज/नांदेवर। जहां एक ओर प्रशासन द्वारा क्षेत्र के अनेक जगहों पर वैकिंग प्यांट लगाकर वाहनों की वैकिंग तो की जा रही है, मगर इसके बाद भी जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा ऐसे वाहनों को नजर अंधाज किया जा रहा है जो वर्षों से बगैर नम्बर प्लेट के दौड़ रहे है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो टैक्टर क्षेत्र में रेत, मृकृज का अवैध उत्खनन लगातार हो रहा है, एक तरफ जहां कमी कमी विभाग द्वारा इस ओर कार्यवाई की जा रही है। वहीं अवैध उत्खनन करने वाले अपने उत्खनन के दौरान अधिकांश रेत कोरोबारी उन टैक्टरों को उपयोग में ला रहे है जिनमें नम्बर नही लिखा हुआ है, इस प्रकार से बगैर नम्बरों के टैक्टरों से दुलाई कराने के चलते जहां एक तरफ राजस्व को लाखों का नुकसान हो रहा है। वहीं इस पर अभी तक आर टी ओ विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नही किये जाने कारण इन टैक्टर वालों के हैसले बुलंद है, क्षेत्र की सड़कों पर इस प्रकार से सैकड़ो ऐसे टैक्टर बगैर नम्बर चल रहे है, जिनमें देखा जावे तो अधिकश अवैध उत्खनन के कार्य में संलिप्त है; टैक्टरों में जहां एक तरफ बिना नम्बर होने के चलते दुर्घटना के बाद इनकी पहचान करना मुश्किल हो जाती है।



